

## उत्तर-पूर्व में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की वफिलता

### चर्चा में क्यों?

केंद्र सरकार की एक प्रमुख योजना, 'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना' (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana- PMFBY) उत्तर-पूर्व के राज्यों में वफिल साबित हो रही है। गौरतलब है कि इस योजना के तहत उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिये सालाना 1,400 करोड़ रुपए रखे गए थे, जबकि पिछले साल केवल 8 करोड़ रुपए ही खर्च किये गए।

### प्रमुख बट्टि

- सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि चार उत्तर-पूर्वी राज्य- अरुणाचल प्रदेश, नगालैंड, मणिपुर और मज़ोरम इस योजना के तहत शामिल ही नहीं हैं।
- बीमा की कमी की वज़ह से मक्का बोने वाले हज़ारों किसान तबाही की कगार पर हैं क्योंकि फॉल आर्मीवर्म ने फसलों को काफी नुकसान पहुँचाया है।

### कारण क्या है?

- बीमा के संबंध में पूर्वोत्तर राज्य कई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं जिनमें नमिनलखिति प्रमुख हैं-
  - बीमा कंपनियों की कम दलिचस्पी।
  - राज्य बजट की कमी के कारण प्रीमियम के अपने हसिसे का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं।
- प्रशासनिक लागत अधिक होने के कारण बीमा कंपनियों इन राज्यों में रुचि नहीं ले रही हैं। बीमा कंपनियों को इसमें दलिचस्पी इसलिये भी नहीं है क्योंकि इस क्षेत्र में कवरेज बहुत सीमति है।
- इन राज्यों के लिये विशेष रूप से ग्राम पंचायत और ब्लॉक स्तर पर उचित भूमरिकॉर्ड के साथ ही पछिली उपजों के आँकड़े भी उपलब्ध नहीं हैं।
- कई फसलों के लिये आवश्यक क्रॉप कटगि एक्सपेरिमेंट (Crop Cutting Experiments- CCEs) करना भी मुश्कल है।

### क्रॉप कटगि एक्सपेरिमेंट

- क्रॉप कटगि एक्सपेरिमेंट की सहायता से फसलों की उपज का उचित और सटीक अनुमान प्राप्त किया जाता है।
- पूर्वानुमान संबंधी बुनयिदी ढाँचे की कमी ने भी इन राज्यों में मौसम आधारित बीमा योजना की राह में बाधा उत्पन्न की है।
- 'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना' अधिसूचित फसलों के लिये फसल ऋण/केसीसी खाते का लाभ उठाने वाले कर्ज़दार किसानों हेतु अनविर्य है, जबकि अन्य दूसरों के लिये स्वैच्छिक।
- यहाँ इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिये कि असम को छोड़कर पूर्वोत्तर में कर्ज़ लेने वाले किसानों की संख्या भी बहुत कम है।

## प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)

'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना' 18 फरवरी, 2016 को शुरू की गई थी। इस योजना का संचालन कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। यह फसल खराब हो जाने की स्थिति में एक व्यापक बीमा कवर प्रदान करती है जिससे किसानों की आय स्थिर करने में मदद मिलती है।

### मुख्य विशेषताएँ

- इस योजना के तहत खरीफ, रबी तथा वार्षिक वाणज्यिक एवं बागवानी फसलों को शामिल किया गया है।
- इसमें खरीफ की फसल के लिये कुल बीमति राशिका 2% तक का बीमा प्रभार, रबी हेतु 1.5% तक तथा वाणज्यिक व बागवानी फसलों के लिये बीमति राशिका 5% तक का बीमा प्रभार नशिचति किया गया है।

- किसानों की प्रीमियम राशिका एक बड़ा हिस्सा केंद्र तथा संबंधित राज्य वहन करता है। बीमति किसान यदा प्राकृतिक आपदा के कारण बोहनी नहीं कर पाता है तो भी उसे दावा राशिका भलि सकेगी।
- इस योजना में स्थानीय स्तर पर हानिका स्थिति में केवल प्रभावति किसानों का सर्वे कर उन्हें दावा राशिका प्रदान की जाएगी। योजना में पोस्ट हार्वेस्ट नुकसान को भी शामिल कया गया है।
- योजना में टेकनोलॉजी (जैसे रिमोट सेंसिंग) इस्तेमाल कर फसल कटाई/नुकसान का आकलन शीघ्र व सही तरीके से कया जाता है, ताकि किसानों को दावा राशिका त्वरति रूप से मलि सके।

## प्रक्रया क्या है?

- PMFBY के परिचालन दिशा-निर्देशों के तहत राज्य सरकारों को फरवरी के शुरू में बीमा कंपनियों के चयन के लिये बडि शुरू करनी होती है, यह प्रक्रया नए फसल वर्ष शुरू होने से थोड़े पहले शुरू करने की व्यवस्था की जाती है।
- इसके बाद सभी प्रासंगिक विवरणों को शामिल करने वाली एक अधिसूचना जारी की जाती, जिसके अंतर्गत फसलों सहति विभिन्न कषेत्रों में परिचालन करने वाली कंपनियों, कषतपूरतिका स्तर और औसत उपज (जसिके मुआवजे की गणना की जाती है), बीमा राशिका वास्तविक प्रीमियम दर एवं इस पर सब्सडी आदि के बयारे को मार्च (खरीफ के सीजन) तथा सतिंबर (रबी के सीजन) के संदर्भ में तैयार कया जाता है।
- किसानों से प्रीमियम प्राप्त करने के लिये कट ऑफ तथियाँ (उन्हें बीमा के लिये पात्र बनाना) 31 जुलाई (खरीफ के लिये) और 31 दसिंबर (रबी) हैं।
- इसके अतिरिक्त किसानों द्वारा चुकाए जाने वाले प्रीमियम की अंतिम तथिका जुलाई 31 (खरीफ के लिये) तथा दसिंबर 31 (रबी के लिये) निर्धारति की गई है।
- राज्यों द्वारा अगस्त-सतिंबर (खरीफ का सीजन) में प्रीमियम सब्सडी योगदान का पहला इंस्टालमेंट जारी कया जाता है तथा शेष राशिका 50 फीसदी भुगतान नवंबर-दसिंबर तक कया जाता है। इसी प्रकार क्रमशः जनवरी-फरवरी और अप्रैल-मई में संबंधित रबी सीजन की पहली कषित जारी कया जाने की उम्मीद होती है।
- इसके अलावा, उन्हें उपज के आकलन के लिये हर गाँव/ग्राम पंचायत में न्यूनतम चार, प्रत्येक तालुका/तहसील/ब्लॉक में 16 और प्रत्येक जिले में 24 CCEs पूर्ण करने होते हैं।
- CCEs आधारति उपज डेटा कटाई के एक महीने के भीतर बीमा कंपनियों को जमा कया जाता है, जो खरीफ फसल के लिये अक्टूबर-दसिंबर और रबी फसल के लिये अप्रैल-जून के दौरान तैयार कया जाता है।
- बदले में कंपनियाँ उपज डेटा प्राप्त होने के तीन हफ्तों में अंतिम दावों का अनुमोदन और भुगतान करने जैसे कार्य संपन्न करती हैं।
- यदा राज्य खरीफ और रबी की फसल के लिये क्रमशः जनवरी और जुलाई तक प्रीमियम सब्सडी के अपने पूरे हिस्से के साथ उपज डेटा उपलब्ध करा देते हैं तो किसान उचित समय के भीतर अपने फसल संबंधी दावों का भुगतान प्राप्त कर सकते हैं।
- केंद्रीय कृषि मंत्रालय के एक शीर्ष अधिकारी द्वारा प्रदत्त जानकारी के अनुसार, बीमा कंपनियाँ तब तक इन दावों के विषय में कोई कार्यवाही नहीं करती हैं जब तक उन्हें पूरा प्रीमियम भुगतान तथा फसल नुकसान के संबंध में उपज डेटा नहीं मलि जाता है।

इस विषय के संबंध में और अधिक जानकारी के लिये नीचे दिये गए लिंकों पर क्लिक करें:

[कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा कये गए सुधार एवं संभावति प्रभाव](#)

[क्या कृषि आय पर कर लगाया जाना चाहिये?](#)

[कृषि को व्यावहारिक और लाभकारी बनाने हेतु 12 पहलें](#)

[प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना \(पीएमएफबीवाई\) के कार्यान्वयन के लिये राज्यों में फसल बीमा कंपनियों को स्थापति करने की मंजूरी](#)

[प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में सुधार की आवश्यकता](#)

[कृषि संकट सुधार हेतु स्मार्ट समाधान](#)

[कृषि पुनरुद्धार की आवश्यकता क्यों?](#)

स्रोत- द हिंदू

